The Congress Party has theoretically withdrawn its support. Does he not feel that by the stand that the Congress Party has taken, it has undermined the democratic process of this country, that you are reduced to the state when the ruling party cannot constitute quorum. Let the Prime Minister respond to it.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I want to make a point. The Prime Minister is saying that... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No point during Question Hour... (*Interruptions*)... Mr. Ghosh, you are a senior man. Why are you...(*Interruptions*)...Question Hour is important.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, my question is without sufficient support how can they run the Government... (*Interruptions*)...

SHRI DIPEN GHOSH: One scenario only is Government is presenting vote-on-account... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The world will decide it. But let them not say that we behaved like... (*Interruptions*)...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, the issue is the Congress party by its action or inaction has reduced democracy to a farce; and has reduced Parliament into a mockery. I am not blaming the Government at all. I blame the master of this Government, Rajiv Gandhi and his party.

MR. CHAIRMAN: Rajiv Gandhi is not a member of this House. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: All right, I blame the Congress party... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Now I want to repeat, whether the Congress party is making a mockery of democracy or not, let us not make a mockery of democracy... (*Interruptions*)...I am not holding a brief for anybody. My brief is for this House. When I am expressing this, I am expressing it on behalf of all of you because I represent all of you. The world will judge what the Congress party did or who did it but let not the world say that the House of Elders, the Rajya Sabha which had long, glorious traditions-very eminent people have sat here—small people like me and some of you, have lowered this House. So for God's sake, let us carry on with the work. As for which party is doing it, it is in the Press and everybody knows it. But by your statements here, it does not help at all... (*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Out of deference to you... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, deference to democracy... (*Interruptions*)...I am nothing.

Mr. Mahajan, put your supplementary.

Poor Customs revenue from Nhava Sheva Port

*143. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:†

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) Government's attention has been drawn to the news item entitled: "Poor Customs revenue from Nhava Sheva Port" which appeared in the Indian Express, New Delhi dated 15th February, 1991 indicating that the port handled only around 15 ships a month as against 150 ships at Bombay port, resulting in lower revenue due to poor infrastructure and shortage of staff;

(b) whether it is a fact that exhorbitant value of real estate in the port premises is a disincentive to the clearing agents opening their offices; whether the port charges are far higher than that levied at Bombay main port;

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

(c) if so, what steps Government propose to take to remove the bottlenecks to improve the revenue collection and what would be the time-frame for removal of the bottlenecks?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, the value of real estate in Jawahar Lal Nehru Port is not acting as a disincentive.

Yes Sir, port charges in Jawahar Lal Nehru Port are generally higher than in Bombay Port.

(c) The Port is taking all steps to attract traffic to the Port. This is an ongoing process. With expected improvement in traffic Customs revenue is also likely to increase.

श्री प्रमोद महाजन : प्रश्न क्रमांक 143...

श्री सभापति : उन्होंने जवाब दे तो दिया है कि स्टेटमेंट इज़ लेड ऑन दि टेबल ऑफ दि हाऊस ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, पता नहीं पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने तक सरकार रहेगी या नहीं रहेगी...

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, चाहे सरकार रहे या न रहे ।

श्री चतुरानन मिश्र : यह प्रश्न कहां है कि रहेगी या नहीं। प्रश्न है कि है कि नहीं ।

श्री प्रमोद महाजन : मैं तो मानता हूं कि फिलहाल है नहीं तो चन्द्रशेखर जी यहां स्ट्रेंजर बन जाते ।

श्री चन्द्रशेखर : इसलिए सरकार है ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मुंबई के निकट बना गया जवाहर लाल नेहरू पत्तन, यह मुंबई पत्तन से अधिक उपयुक्त होगा, इस आधार पर करोड़ों का खर्चा करके बना था, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसका जितने ठीक ढंग से उपयोग होना चाहिए, हो नहीं रहा है और मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन में पत्तन प्रभार मुंबई पत्तन की तुलना में अधिक है । मैं यह जानना चाहूंगा कि मुंबई में कितना है और जवाहर लाल नेहरू पत्तन में कितना प्रभार है और जवाहर लाल नेहरू पत्तन में प्रभार अधिक होने के कारण क्या हैं ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : सर, मैंने इसमें जिक्र तो किया है, लेकिन यह लिस्ट है आइटमवाईज, लंबी लिस्ट है । It is very long.

श्री सभापति : लिस्ट है, तो आप इसको टेबुल पर रख दीजिएगा ।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : ठीक है, सर, मैं इसको सदन के पटल पर रख दूंगा ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि कारण क्या हैं ?

श्री सभापति : आप कारण बता दीजिए ।

श्री प्रमोद महाजन : यह मुंबई पत्तन से जवाहर लाल नेहरू पत्तन में अधिक क्यों है ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : अधिक इसलिए है कि जवाहर लाल नेहरू पोर्ट नया बनाया है । उसके ऊपर जो लागपत लगी है, वह 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगी है और उस में हम जो फेसिलिटीज दे रहे हैं, उस फेसिलिटीज के मुताबिक मुंबई पोर्ट और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट की तुलना करेंगे तो जो कमोडिटीज-वाइज चार्जेज हैं, वह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वेटिंग चार्जेज जो है लगता नहीं, वेटिंग पीरेड नहीं है और हेंडलिंग की फेसिलिटीज

इतनी अधिक है, जिससे कि शिप खाली करके जाएगा तो उसको बंबई पोर्ट से न्हावाशिवा पोर्ट में लागत ओवर-ऑल कम पड़ती है ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि वहां फेसिलिटीज ज्यादा है इसलिए ज्यादा चार्जेज हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे यह समझने में आश्चर्य होता है कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन ठीक ढंग से चल नहीं रहा है । वहां, जहां 150 जहाज जाने चाहिए 15 भी नहीं जा रहे । मुम्बई में सबसे अधिक जहाज आ रहे हैं मुम्बई पत्तन का भार कम करने के लिए ही जवाहर लाल नेहरू पत्तन का निर्माण हुआ था । लेकिन वहां जहाज कम जा रहे हैं । मेरी समझ में इसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा दाम देकर के और जहाज कम होते जा रहे हैं । आप सुविधा बढ़ाएं और जहाज वहां न जाएं तो उस सुविधा का क्या उपयोग । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसके पीछे तर्क क्या है ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तर्क की बात कही थी कि उसके ऊपर ज्यादा लागत लगी है और उस पर ज्यादा फेसिलिटीज दे रहे हैं । तो इससे जो हम ओवर-ऑल गिनती करते हैं, ज्यादा लागत है, कमोडिटीजवाइज थोड़ा ज्यादा चार्ज है, लेकिन ओवरऑल जो बेर्थिंग और हैंडलिंग चार्जेज हैं, उससे बच जाते हैं । . . .

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि वहां जहाज जा रहे हैं, बेर्थिंग टाइम ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है तो वहां कमी क्यों करते जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : बंबई पोर्ट और न्हावाशिवा पोर्ट का नपेरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उधर 55 बर्थस हैं बंबई में और यहां 5 बर्थस हैं । तो 5 बर्थस और 55 बर्थस, उन दोनों की तुलना क्या । न्हावाशिवा में एक महीने में 15 शिप दे सकते हैं तो उधर क्या करते हैं कि ज्यादा करते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, उत्तर में एक दूसरी बात कही है कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन की ओर अधिक यातायात आकर्षित हो, इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या विशेष उपाय हैं, जिसके कारण इसमें ज्यादा जहाज आएं, जिस दृष्टि से सरकार सोच रही है ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए उधर जो कुछ डेफिसियेंसिस थीं, उसके बारे में पर्टिकुलरली इम्प्रूवमेंट आफ स्टोकयार्ड और पार्किंग फेसिलिटीज कम थीं और बंबई से जो लोग पोर्ट का उपयोग करने के लिए आते जाते थे, उनके आने-जाने की सुविधा कम थी, तो वह सुविधाएं बढ़ाई गई हैं । Nine launches are already running between Bombay and Nhava Sheva. Likewise, we have taken so many actions for that.

श्री सभापति : बर्थ भी बढ़ाएंगे क्या ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : बर्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज जितने बर्थ हैं, उसका भी न्हावाशिवा पर पूरा उपयोग नहीं हो सका ।

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, the title of the question is 'Construction of Roads'. Taking advantage of this title, I would like to know... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: We are on question No. 143. This is about Nhava Sheva and Bombay ports.

SHRI MURASOLI MARAN: They have built a very nice port, that is, the port

of Government in the Congress support. But that port has been bombarded by aeril bombing, by Mr. Rajiv Gandhi. Therefore, the lifeline is cut away. The supply-lines are cut away. I would like to know whether they are doing anything to repair the port, so that the harbour may be rendered useful or whether they are going to desert it and run away. (*Interruptions*).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It sounds like a cinema script which they used to write. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Shri Chaturanan Mishra: (*Interruptions*). आप सवाल पूछिए।

श्री चतुरानन मिश्र : अब यह लोग बातचीत समाप्त करें तब न। जब सुब्रह्मण्यम जी आ जाते हैं तो हमारे हाऊस की रौनक बढ़ जाती है।

श्री सभापति : यह चाचा-भतीजे का मामला है, इसमें मैं क्या बोलूं।

श्री चतुरानन मिश्र : इनके आने ही से रौनक बढ़ जाती है। थोड़ा लोगों को इंसेटिव हो जाता है बोलने लगते हैं उनके आने ही से। तो किसी-किसी व्यक्ति को एट्रेक्शन होता है सब को तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो इनको है।

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं या दूसरी हैं वह सब अंडर केपेसिटी काम करती हैं। उसके चलते हमारी इकोनौमी बर्बाद हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार के नोटिस में यह बात कब आयी कि इस तरह से वहां जितने जहाज़ जाने चाहिएं वह नहीं जा करके बहुत कम तादाद में जहाज वहां पर जा रहे हैं। यह नोटिस में कब आया और उसका कारण सरकार ने क्या सोचा? जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि उसकी रेमेडी के लिए क्या-क्या मेजर्स लिये? इन तीनों बिन्दुओं पर स्थिति साफ करें, मंत्री महोदय कि कब आपके नोटिस में आया कब आपने इसकी जांच करवायी और जांच में क्या-क्या आया और क्या-क्या मेजर्स लिये?

श्री मनुभाई कोटाडिया : अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा विस्तृत इस बारे में कहूंगा कि यह पोर्ट नया है। मई, 89 में इसका इनआगरेशन हुआ। उसमें शुरू-शुरू में जो तकलीफें होती हैं, जो ट्रबल होती हैं नेचुरली वह इसमें भी है और चालू है। सर पोर्ट का जो लोग उपयोग करते हैं, जो लोग शिप पर हैं, उसके जो एजेंट्स हैं वह सब, बम्बई से इतनी जल्दी नावल सेवा नहीं जाती है क्योंकि उधर जो फैसिलिटी उन लोगों को चाहिए और जो खुद को करनी चाहिए और उसको करने की जरूरत थी वह इतनी जल्दी नहीं हो सकती और उनका जो पूरा एस्टीब्लेशमेंट बम्बई में हो गया वह लोग उधर रहने के लिए उनके आफिस खोलने के लिये इतनी जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं थे और जैसा मुरासोली जी ने कहा कि सरकार के लक्ष्य में यह बात कब आयी? तो यह बात सरकार के लक्ष्य में पहले से थी और जो 5.90 मिलियन टन की ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है उसके सामने इस साल 2.40 मिलियन टन की थी। जनवरी के आखिर तक जो हुआ है वह 1.65 मिलियन टन है और इस साल के अंत में 31 मार्च तक हम ऐसा मानकर चलते हैं, वह 2.20 मिलियन टन हो जावेगा 2.40 मिलियन टन के विरुद्ध। यह नया पोर्ट है, यह होने की संभावना थी, वह लक्ष्य में ही थी और ज्यादा ट्रैफिक वापिस करने के लिए उधर जो कुछ सुविधायें बढ़ाने की जरूरत थी वह सुविधायें बढ़ायी हैं। उसके लिये आफिस कम्प्लैक्स बनाया है और उसके लिये टेली कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी नहीं थी तो वह कर दी गयी है और पोर्ट के, कस्टम के जो आफिस दूर थे, वह उनके पास हम लाये हैं। उधर लोग जो और सुविधा चाहते हैं पूरी सुविधा उनको दे रहे हैं। बम्बई से आने के लिए बसेज की भी व्यवस्था की गयी है और बम्बई से लांचर की व्यवस्था भी की गई है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैस्टर्न कोस्ट पर जब करांची पाकिस्तान में चला गया उसके बाद कांडला पोर्ट को सरदार पटेल साहब ने

डवलप किया। तो मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि कांडला पोर्ट के चार्जेज में और न्हाव शेवा च र्जेज में कितना अंतर है? यह ज्यादा है या कम है?

श्री मनुभाई कोटाडिया : अध्यक्ष महोदय, कांडला पोर्ट के जो च र्जेज हैं वह लिस्ट आज मेरे पास नहीं है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आप दे देंगे न?

श्री सभापति : आप आपस में बात कर लेना।

श्री अनन्तराय देव शंकर दवे : यह मेजर पोर्ट का क्वेश्चन है। उनके पास जानकारी तो होनी चाहिए।

श्री सभापति : न्हावा शेवा का सवाल है, उसमें पूरे पोर्ट का पूछेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी।

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: It is regretted that the hon. Minister has not correctly replied to the question while assessing the Nhava Sheva Port or Jawaharlal Nehru Port. It is a fact that this Port has been conceived to supplement Bombay Port since Bombay Port is facing congestion. And it is not a fact that the Port came into operation in the year 1989. It was only inaugurated in the year 1989 but functioned prior to that. Will the Minister be pleased to state whether it is a fact that the machinery, imported from South Korea, fitted into the Nhava Sheva Port, is not functioning well? That is the reason why only 8.5 per cent of utilisation of port capacity has been done in the Nhava Sheva Port last year.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, it is a fact that certain machinery is not working well. Since it is a new machinery, since it is a new concept, we are trying to rectify it.

Delay in environmental clearance of the cases sent by the State Governments

*144. SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:†

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to reduce the delay in environmental clearance of the cases sent by State Governments by eliminating some of the middle level bureaucratic set up, and raising of queries at various stages; and

(b) whether it is a fact that the number of proposals pending from Gujarat are around 20 and a number of them are pending since long?

THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DR. SUBRAMANIAN SWAMY): (a) The existing procedure for environmental clearance of development projects is already streamlined and a final decision in all cases where complete details are furnished is taken within a maximum period of three months. In many cases, decision is taken in a much shorter time.

(b) Yes, Sir. Delay in processing and deciding cases is the result of non-submission of requisite data and action plans.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, the answer in (b) has contradicted the answer in (a) because in the beginning it is said that it takes time in making a decision because answers are not given by the States concerned. Here this is the moot question. You are putting so many queries, intermediate queries; it goes on for years and my precise question is not answered here. There are 20 proposals pending from Gujarat. Since how long are they pending? I have asked this question. Why are they not cleared? Now the

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chiman Bhai Mehta.